



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार 6 अक्तूबर, 2012/14 आश्विन, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA -171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 3rd October, 2012

No.HHC/GAZ/14-281/2005.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex post facto sanction of 10 days medical leave w.e.f. 8.9.2012 to 17.9.2012 in favour of Smt. Gurmeet Kaur, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC, Bilaspur.

Certified that Smt. Gurmeet Kaur has joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Gurmeet Kaur would have continued to hold the post of Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC, Bilaspur, but for her proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001**NOTIFICATION***Shimla, the 3rd October, 2012*

No. HHC/GAZ/14-290/2006.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of one day's commuted leave for 20.9.2012 in favour of Shri Sidharth Sarpal, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Kandaghat, District Solan, H.P.

Certified that Shri Sidharth Sarpal has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Sidharth Sarpal would have continued to hold the same post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Kandaghat, District Solan, H.P. but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001**NOTIFICATION***Shimla, the 3rd October, 2012*

No. HHC/GAZ/14-290/2006.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant three days' earned leave w.e.f. 3.10.2012 to 5.10.2012 with permission to prefix Gazetted holiday falling on 2.10.2012 in favour of Shri Sidharth Sarpal, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Kandaghat, District Solan, H.P.

Certified that Shri Sidharth Sarpal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Sidharth Sarpal would have continued to hold the post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Kandaghat, H.P. but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001**NOTIFICATION***Shimla the 3rd October, 2012*

No. HHC/GAZ/14-290/2006.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant two days' earned leave for 17.10.2012 and 18.10.2012 in favour of Shri Sidharth Sarpal, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Kandaghat, District Solan, H.P.

Certified that Shri Sidharth Sarpal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Sidharth Sarpal would have continued to hold the post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Kandaghat, H.P. but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 4th October, 2012

No.HHC/Admn.16 (13)74-VII.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Bhagat Ram, Advocate, Chopal, as Oath Commissioner at Chopal, H.P. for a period of two years, with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, 01st October, 2012

No.HHC/Admn.3(390)/94.—**06 days earned leave** on and w.e.f. 01.10.2012 to 06.10.2012 with permission to affix Sundays falling on 30.09.2012 and 07.10.2012 is hereby sanctioned in favour of Shri Rajesh Kumar Sharma, Court Master of this Registry.

Certified that Shri Rajesh Kumar Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Rajesh Kumar Sharma would have continued to officiate the same post of Court Master, but for his proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 3 अक्टूबर, 2012

संख्या: ई0एक्स0एन0-एफ(10)-7/2011(i).—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 6 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के साथ पठित धारा 63 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए इस विभाग की अधिसूचना संख्या ई.एक्स.एन.-एफ(5)-4/2005, तारीख 2 दिसम्बर, 2005 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में, तारीख 7 दिसम्बर, 2005 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2005 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (सातवां संशोधन) नियम, 2012 है ।

(2) ये नियम ई-राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. अध्याय 15 का जोड़ा जाना.—हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2005 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) के अध्याय-14 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"अध्याय-15

विनिर्माण के लिए औद्योगिक आगतों, कच्ची सामग्रियों और पैकिंग सामग्रियों पर कर की रियायती दर का विनियमन करने की प्रक्रिया

96. औद्योगिक आगतों पर कर का उद्ग्रहण.—इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, अनुसूची 'क' के भाग-2-क की प्रविष्टि संख्या 55 के अधीन पहले से ही सूचीबद्ध से अन्यथा औद्योगिक आगतों, कच्ची सामग्री और पैकिंग सामग्री के, किन्तु हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 11 की उपधारा (8) में यथा विनिर्दिष्ट माल को अपवर्जित करके, विक्रय पर पांच प्रतिशत की दर से कर उद्ग्रहीत किया जाएगा ।

97. रियायती कर के उद्ग्रहण के लिए प्रक्रिया और शर्त.—नियम 96 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, औद्योगिक आगतों, कच्ची सामग्री और पैकिंग सामग्री पर निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों के अधीन पांच प्रतिशत की दर से कर का उद्ग्रहण किया जाएगा, अर्थात्:—

- (i) माल, जो केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन क्रय की जाने वाली औद्योगिक आगत, कच्ची सामग्री या पैकिंग सामग्री है;
- (ii) औद्योगिक आगतों, कच्ची सामग्रियों या पैकिंग सामग्रियों का ऐसा विक्रय, जो रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी द्वारा अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी और औद्योगिक इकाई को किया गया है;
- (iii) विक्रीत माल सम्बद्ध जिला के निर्धारण प्राधिकारी द्वारा प्ररूप-43 में, हकदारी प्रमाण पत्र में, सम्यक् रूप से विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (iv) विक्रीत माल, क्रय करने वाली औद्योगिक इकाई द्वारा, हिमाचल प्रदेश राज्य में विक्रय के लिए या अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य या देश के राज्य क्षेत्र से बाहर, निर्यात के अनुक्रम में

क्रय के लिए माल का विनिर्माण करने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया गया है; और

- (v) रियायती दर, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (सातवां संशोधन) नियम, 2012 से सम्बन्धित अधिसूचना के जारी होने की तारीख से, सम्बद्ध जिला के निर्धारण प्राधिकारी (जिला प्रभारी) द्वारा प्ररूप-43 में हकदारी प्रमाण पत्र जारी करने के अध्यक्षीन, समस्त उपयुक्त औद्योगिक इकाइयों को लागू होगी:

परन्तु प्ररूप-43 में सम्बद्ध जिला के निर्धारण प्राधिकारी (जिला प्रभारी) द्वारा तब तक कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा, जब तक उसे प्रदान करने के लिए जहाँ औद्योगिक इकाई रजिस्ट्रीकृत है, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उद्योग विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार, या अन्य मामलों में निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश या इस निमित्त उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत उसके नामनिर्देशिती से, ऐसे उद्यमी द्वारा प्राप्त, प्ररूप-44 में प्रमाण-पत्र संलग्न न किया गया हो:

परन्तु यह और कि हकदारी प्रमाण पत्र प्रदान करने के आवेदन को, सम्बद्ध जिला के निर्धारण प्राधिकारी (जिला प्रभारी) द्वारा तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा, जब तक सरकारी खजाना में 500/- रूपए मुख्य शीर्ष 0040-विक्रय एवं व्यापार पर कर, 800-अन्य प्राप्तियां-03-अन्य प्राप्तियां में जमा करने की रसीद संलग्न न हो या आबकारी एवं कराधान विभाग की वेबसाईट के माध्यम से ऑनलाइन संदाय न कर दिया गया हो ।

- (vi) यदि, कोई प्रमाण पत्र, यथास्थिति, प्ररूप-43 और प्ररूप-44 में गलत, अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण पाया जाता है या अधिनियम के अधीन विवरणी सहित नहीं दिया गया है तो कर, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित पूरी दरों पर उद्गृहीत किया जाएगा ।

98. इस अध्याय के अधीन हकदारी प्रमाणपत्र.—बुअरिज, डिस्टिलरीज, नॉन फ्रूट वेसड वाइनरीज एण्ड बॉटलिंग प्लान्ट्स (देसी शराब और भारतीय निर्मित विदेशी शराब दोनों के लिए) के सिवाए, हिमाचल प्रदेश में विक्रय या अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य या देश के राज्यक्षेत्र से बाहर निर्यात के अनुक्रम में, विक्रय के लिए माल के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग के लिए विनिर्माताओं द्वारा औद्योगिक आगंतों, कच्ची सामग्री और पैकिंग सामग्री के क्रय पर रियायती कर की दर की प्राप्ति, जहाँ इकाई रजिस्ट्रीकृत है, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र या अन्य मामलों में निदेशक, उद्योग, हिमाचल प्रदेश द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत उसके नामनिर्देशिती से प्ररूप-44 में प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात्, सम्बद्ध जिला के निर्धारण प्राधिकारी (जिला प्रभारी) द्वारा हकदारी प्रमाणपत्र जारी करने के अध्यक्षीन होंगी ।

99. कर, शास्ति और ब्याज की वसूली.—किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (सातवां संशोधन) नियम, 2012 में विनिर्दिष्ट शर्तों और निर्बन्धनों में से किसी के भंग होने के कारण, व्यौहारी द्वारा कर और ब्याज सहित शास्ति की कोई रकम, यदि संदेय है, तो वह सम्बद्ध जिला के निर्धारण प्राधिकारी (जिला प्रभारी) द्वारा वसूलीय होगी, जो सम्बद्ध व्यौहारी के स्टॉक में माल या अन्य चल सम्पत्ति के व्ययन द्वारा कर, शास्ति और ब्याज की वसूली प्रवर्तित करने के लिए सशक्त होगा ।

100. हकदारी प्रमाणपत्र को संशोधित, स्थगित, प्रत्यावर्तित और रद्द करने की शक्ति.—सम्बद्ध जिला का निर्धारण प्राधिकारी (जिला प्रभारी) व्यौहारी को प्रदान किए गए हकदारी प्रमाण पत्र को संशोधित, स्थगित, प्रत्यावर्तित और रद्द करने के लिए सशक्त होगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अधिनियम के अधीन ऐसे आदेश को पारित करने के लिए सक्षम उच्चतर प्राधिकारी के किसी आदेश के अध्यक्षीन हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (सातवां संशोधन) नियम, 2012 की शर्तों में से किसी को भंग किया गया है। ऐसा कोई आदेश व्यौहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा ।

101. इस अध्याय के अधीन शास्ति का उद्ग्रहण.—जो कोई भी, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (सातवां संशोधन) नियम, 2012 के किन्हीं उपबन्धों का कर की अपवंचना करने के आशय से उल्लंघन करता है, तो सम्बद्ध जिला का निर्धारण प्राधिकारी (जिला प्रभारी) ऐसे व्यौहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् देय कर की रकम के पचास प्रतिशत से अनधिक राशि, शास्ति स्वरूप अधिरोपित करेगा किन्तु जो देय कर की रकम के शतप्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

102. इस अध्याय के अधीन अपराधों का शमन.—सम्बद्ध जिला का निर्धारण प्राधिकारी (जिला प्रभारी) अन्य अपराधों का, जिनमें कर के अपवंचन के प्रत्येक ऐसे उल्लंघन के लिए पाँच सौ रूपए की शास्ति का उद्ग्रहण अन्तर्वलित नहीं है, शमन कर सकेगा । व्यौहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना, कोई भी शास्ति उद्ग्रहित नहीं की जाएगी ।

103. विवरणियों के साथ प्ररूप-43 और प्ररूप-44 का प्रस्तुत किया जाना.—प्रत्येक व्यौहारी, जिसे प्ररूप-43 में हकदारी प्रमाणपत्र जारी किया गया है, निर्धारण वर्ष के लिए उसकी प्रतियाँ और मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक विवरणी सहित प्ररूप-44 में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा ।

3. प्ररूप-43 और प्ररूप-44 का जोड़ा जाना.—उक्त नियमों में प्ररूप-42 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप जोड़े जाएंगे, अर्थात्:—

"प्ररूप-43

(नियम 97, 98, 100 और 103 देखें)

हकदारी प्रमाण पत्र

(सम्बन्ध जिला के निर्धारण प्राधिकारी (जिला प्रभारी) द्वारा जारी किया जाएगा)

संख्या:—

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्ज..... (उद्यमी/औद्योगिक इकाई का नाम और पता), जिसने प्ररूप-44 में, जहां औद्योगिक इकाई रजिस्ट्रीकृत है, वहां के सम्बन्धित महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार से या अन्य मामलों में, यथास्थिति निदेशक (उद्योग), हिमाचल प्रदेश या उसके द्वारा इस निमित्त समयक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति से प्रमाण पत्र दिया है, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005/केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन जिला....., हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रीकरण संख्या..... के साथ रजिस्ट्रीकृत किया गया है। प्ररूप-44 में प्रमाणपत्र की परीक्षा करने के पश्चात् तथा पूर्वोक्त अधिनियमों और तदधीन बनाए गए नियमों के सुसंगत उपबन्धों का अध्ययन करने के पश्चात्, पूर्वोक्त उद्यमी/औद्योगिक इकाई के पक्ष में हकदारी प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है ।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि तारीख..... को जारी रजिस्ट्रीकरण संख्या..... वाले हकदारी प्रमाणपत्र के अनुसार, उद्यमी/औद्योगिक इकाई हिमाचल प्रदेश राज्य में विक्रय के लिए या अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य या देश के राज्य क्षेत्र से बाहर निर्यात के अनुक्रम में क्रय के लिए माल का हिमाचल प्रदेश में विनिर्माण के लिए उसके द्वारा औद्योगिक आगतें, कच्चे माल और पैकिंग सामग्री के रूप में उपभोग हेतु (अनुसूची 'क' के भाग 2-क की प्रविष्टि संख्या 55 के अधीन सूचीबद्ध के सिवाय) निम्न विनिर्दिष्ट माल क्रय कर सकेगा ।

माल का विवरण

(अनुसूची 'क' के भाग 2-क की प्रविष्टि संख्या 55 के अधीन सूचीबद्ध के सिवाय)

--

3. यह प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात्:-

- (i) माल को स्पष्टतः विनिर्दिष्ट करना आवश्यक है। "और इस प्रकार", "आदि" अभिव्यक्तियों से माल का विनिर्देश अभिप्रेत नहीं होगा और ऐसी अभिव्यक्तियों के कारण कोई रियायत अनुज्ञेय नहीं होगी।
- (ii) इस प्रमाण पत्र में तब तक कोई संशोधन विधिमान्य नहीं होगा जब तक संबद्ध जिला के निर्धारण प्राधिकारी (जिला प्रभारी) द्वारा आदेशित और अनुप्रमाणित न किया गया हो;
- (iii) इस प्रमाण पत्र का धारक इसे तब अभ्यर्पित करेगा जब संबद्ध जिला के निर्धारण प्राधिकारी (जिला प्रभारी) या किसी अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने को कहा जाए;
- (iv) प्रमाणपत्र या उसकी अधिप्रमाणित प्रति, आबकारी एवं कराधान विभाग के किसी अधिकारी, जो आबकारी एवं कराधान अधिकारी से नीचे की पंक्ति का न हो, के मांगने पर तत्काल प्रस्तुत की जाएगी; और
- (v) यह प्रमाण पत्र एक बार अभिप्राप्त किया जाएगा और तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक इसे रद्द नहीं किया जाता है।

4. यह प्रमाण पत्र तारीख..... से तब तक विधिमान्य रहेगा, जब तक इसे रद्द नहीं किया जाता है।

स्थान.....

तारीख.....

संबद्ध जिला का निर्धारण प्राधिकारी
जिला..... (हिमाचल प्रदेश)

(निर्धारण प्राधिकारी की मुद्रा)

विशेष टिप्पणी:-

हकदारी प्रमाण पत्र, महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जहां इकाई रजिस्ट्रीकृत है, द्वारा प्ररूप 44 में जारी प्रमाण पत्र की परीक्षा करने के पश्चात् संबद्ध जिला के निर्धारण प्राधिकारी (जिला प्रभारी) द्वारा जारी किया जाएगा या अन्य मामलों में निदेशक उद्योग द्वारा, पूर्वोक्त अधिनियमों के अधीन औद्योगिक इकाईयों को जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र और पूर्वोक्त अधिनियम तथा तदधीन बनाए गए नियमों के सुसंगत उपबंधों का अध्ययन करने के पश्चात् जारी किया जाएगा।

प्ररूप-44

(नियम 97, 98 और 103 देखें)

प्रमाण पत्र

(जहां इकाई रजिस्ट्रीकृत है, वहां के जी.एम.डी. आई.सी (महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र) द्वारा या अन्य मामलों में निदेशक, उद्योग हिमाचल प्रदेश द्वारा हस्ताक्षरित और जारी किया जाना है)

संख्या:-

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स..... (नाम और पूरा पता), रजिस्ट्रीकरण संख्या.....
..... तारीख..... के विरुद्ध अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में विक्रय के लिए..... के
निर्माण हेतु औद्योगिक इकाई के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, तथा उक्त औद्योगिक इकाई ने उक्त माल का निर्माण
तारीख.....से प्रारम्भ किया है ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वोक्त औद्योगिक इकाई विद्यमान है तथा पूर्वोक्त मद के विक्रयार्थ
निर्माण में लगी हुई है ।

यह प्रमाण पत्र उत्पाद के प्रारम्भ की तारीख..... से तब तक विधिमान्य रहेगा, जब तक
कि जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा इसे रद्द नहीं किया जाता है ।

तारीख.....

जारी करने वाले प्राधिकारी
के मुद्रा सहित हस्ताक्षर ।

विशेष टिप्पणी:-

यह प्रमाण पत्र महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, जहां औद्योगिक
इकाई रजिस्ट्रीकृत है, द्वारा या अन्य मामलों में, यथास्थिति, निदेशक, उद्योग, हिमाचल प्रदेश या अन्य सक्षम
प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और जारी किया जाएगा । ”।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

*[Authoritative English Text of this Department Notification No. EXN-F(10)-7/2011(i), dated
03-10-2012 required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].*

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 3rd October, 2012

No. EXN-F(10)-7/2011(i).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 63 read with first proviso to sub-section (1) of section 6 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Rules, 2005 notified vide this department notification number EXN-F(5)-4/2005, dated 2nd December, 2005 and published in Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra Ordinary), dated 7th December, 2005 for carrying out the purposes of the said Act, namely:—

1. Short Title.— (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (Seventh Amendment) Rules, 2012.

(2) These shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Addition of CHAPTER-XV.—After CHAPTER-XIV of the Himachal Pradesh Value Added Tax Rules, 2005 (hereinafter referred to as the ‘said rules’), the following CHAPTER shall be added, namely:—

“CHAPTER-XV**PROCEDURE TO REGULATE CONCESSIONAL RATE OF TAX TO MANUFACTURES
ON INDUSTRIAL INPUTS, RAW MATERIALS AND PACKING
MATERIALS**

96. Levy of tax on industrial inputs.—Notwithstanding, anything to the contrary contained in these rules, the tax shall be levied @ 5% on the sale of industrial inputs, raw-materials and packing materials other than those already listed under entry number 55 of Part-II-A of Schedule ‘A’ but excluding the goods as specified in sub-section (8) of Section 11 of Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005.

97. Procedure and Condition for levy of concessional tax.—Notwithstanding, anything contained in rule 96, the levy of tax @ 5% on industrial inputs, raw-materials and packing materials shall be subject to the following restrictions and conditions, namely;

- (i) the goods which are Industrial Inputs, raw materials or packing materials to be purchased under clause (b) of sub-section (3) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956;
- (ii) such sales of Industrial Inputs, raw materials or packing materials are made by registered dealer to other registered and eligible industrial unit;
- (iii) the goods sold are duly specified in the Entitlement Certificate in Form-XLIII issued by the Assessing Authority of the district concerned;
- (iv) the goods sold are used by purchasing industrial unit as raw material to manufacture goods for sale in the State of Himachal Pradesh or sale in the course of inter-State trade or commerce or export out of the territory of the country; and
- (v) the concessional rate shall be applicable to all eligible industrial units from the date of issue of notification regarding Himachal Pradesh Value Added Tax (Seventh) Amendment Rules, 2012 subject to issue of Entitlement Certificate in Form-XLIII by the Assessing Authority of the district concerned (district incharge).

Provided that no certificate in Form-XLIII shall be issued by the Assessing Authority of the district (district incharge) unless the application for the grant of the same is accompanied by the certificate in Form-XLIV obtained by such entrepreneur from the concerned General Manager, District Industries Center of the Department of Industries of Government of Himachal Pradesh where the Industrial unit is registered or in other cases from Director of Industries, Himachal Pradesh or his nominee duly authorised by him in this behalf:

Provided further that the application for the grant of Entitlement Certificate shall not be entertained by the Assessing Authority of the district (district incharge) unless it is accompanied by a deposit receipt of Rs. 500/- in the Government Treasury or payment made online through the website of the Excise and Taxation Department under head of account 0040-tax on sales, trade etc.-800-other receipts-03-other receipts.

- (vi) The tax shall be levied at full rates notified under sub-section (1) of section 6 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (hereinafter referred to as the ‘Act’) if

any of the certificates in Form-XLIII and Form-XLIV, as the case may be, is found to be false, incomplete or defective or is not furnished with return under the Act.

98. Entitlement Certificate under this Chapter.—To avail concessional tax rate on the purchase of industrial inputs, raw-material and packing material by manufacturers for use as raw material to manufacture goods for sale in Himachal Pradesh or sale in the course of inter-State trade or commerce or export out of the territory of the country except Breweries, Distilleries, Non-Fruit Based Wineries and Bottling Plants (both for Country Liquor and Indian Made Foreign Liquor) shall be subject to issue of Entitlement Certificate by Assessing Authority of the district concerned (district incharge) after receipt of certificate in Form-XLIV from General Manager, District Industries Center where the unit is registered or in other cases by the Director of Industries, Himachal Pradesh or his nominee duly authorised by him in this behalf.

99. Recovery of tax, penalty and interest.—Notwithstanding anything to the contrary contained in any law, any amount of tax and penalty including interest, if any payable by the dealer on account of breach of any of the conditions and restrictions specified in Himachal Pradesh Value Added Tax (Seventh Amendment) Rules, 2012 shall be recoverable by the Assessing Authority of the district (district incharge) which shall be empowered to enforce recovery of tax, penalty and interest by way of disposing of goods in stock or any other movable property of the dealer concerned.

100. Power to amend, suspend, restore and cancel Entitlement Certificate.—The Assessing Authority of the district (district incharge) shall be empowered to amend, suspend, restore and cancel the Entitlement Certificate granted to the dealer, if it is satisfied that a breach of any of the conditions of the Himachal Pradesh Value Added Tax (Seventh Amendment) Rules, 2012 has been committed subject to any order of the higher authority competent to pass such order under the Act. No such order shall be passed without affording a reasonable opportunity of being heard to the dealer.

101. Levy of penalty under this Chapter.—Whosoever, contravenes any of the provisions of the Himachal Pradesh Value Added Tax (Seventh Amendment) Rules, 2012, with an intention to evade tax, the Assessing Authority of the district (district incharge) shall impose by way of penalty a sum not less than fifty percentum of the amount of tax due but which shall not exceed hundred percentum of the amount of tax due after giving such dealer an opportunity of being heard.

102. Compounding of offences under this Chapter.— The Assessing Authority of the district (district incharge) may compound other offences in which no tax evasion is involved by levy of penalty of rupees five hundred for each such contravention. No penalty shall be levied without affording a reasonable opportunity of being heard to the dealer.

103. Submission of Form-XLIII and XLIV with returns.—Every dealer who has been issued an Entitlement Certificate in Form-XLIII shall submit the copies of the same and certificate in Form-XLIV with the monthly/quarterly /annual return for the assessment year.

Addition of Forms.— 3. In the said rules, after Form XLII the following Forms shall be added, XLIII and XLIV. namely:—

“FORM –XLIII

(See Rule 97, 98,100 and 103)

ENTITLEMENT CERTIFICATE

[To be issued by the Assessing Authority of the district concerned (district incharge)]

No. _____

This is to certify that M/s _____ (name and address of the entrepreneur/Industrial Unit), who has furnished a certificate in Form-XLIV from the concerned General Manager, District Industries Centre of the Department of Industries of the Government of Himachal Pradesh where the industrial unit is registered or in other cases from Director of Industries, Himachal Pradesh or duly authorized by him in his behalf, as the case may be, has been registered as a dealer under the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005/ Central Sales Tax Act, 1956 with Registration Certificate No. _____ in _____ District, Himachal Pradesh. The Entitlement Certificate is being issued in favour of the aforesaid entrepreneur/industrial unit after examining the certificate in Form-XLIV and after going through the relevant provisions of the aforesaid Acts and rules framed thereunder.

2. This is further to certify that as per this Entitlement Certificate bearing Registration No. _____ issued on _____ (dated), the entrepreneur/industrial unit may purchase the goods specified below (other than those listed under entry no. 55 of Part-II-A of Schedule 'A') for use by him as industrial inputs, raw materials and packing materials in the manufacture in Himachal Pradesh of any goods for sale in the State of Himachal Pradesh, or for sale in the course of inter-State trade or commerce or export outside the territory of India.

DESCRIPTION OF GOODS

(Other than those already listed under entry no. 55 of Part-II-A of Schedule 'A')

--

3. This certificate shall be subject to the following conditions, namely:-

- (i) goods must be clearly specified. The expression "and the like", "etc." shall not amount to specification of goods and no concession shall be permissible on account of such expression;
- (ii) no amendment in this certificate shall be valid unless ordered and attested by the Assessing Authority of the district concerned (district incharge);
- (iii) the holder of this certificate shall surrender it when required to do so by the Assessing Authority of the district concerned (district incharge) or an Appellate or Revisional Authority;
- (iv) the certificate or authenticated copy of it shall be produced immediately on demand by any officer of the Excise and Taxation Department not below the rank of Excise and Taxation Officer; and
- (v) this certificate shall be obtained once and shall be operational until cancelled;

4. This certificate shall be valid from (date) until cancelled.

Place

Assessing Authority of the district
concerned (district incharge)

Date.....

District(HP).

(Seal of the Assessing Authority)

N.B.

The Entitlement Certificate shall be issued by the Assessing Authority of the district concerned (district incharge) after examining the certificate in Form-XLIV issued by General Manager District Industries Centre where the unit is registered or in other cases by Director Industries, the certificate of registration issued to the industrial units under the aforesaid Acts and after going through the relevant provisions of the aforesaid Acts and rules framed thereunder.

FORM-XLIV

(See Rule 97, 98 and 103)

CERTIFICATE

(To be signed and issued by G.M. D.I.C. where unit is registered or in other cases by Director Industries, H.P.)

No.....

This is to certify that M/s _____ (name and full address) is registered as an industrial unit in the office of the undersigned against Registration No. _____ dated _____ for the manufacture of _____ for sale, and that the said industrial unit commenced manufacture of the said goods with effect from _____ (date).

This is also certified that the aforesaid industrial unit is live and engaged in manufacturing of aforesaid item for sale.

This certificate shall be valid from the date of commencement of production w.e.f. Until cancelled by the issuing Authority.

Date

Signature of issuing Authority
with seal.

NB

This certificate shall be signed and issued by the General Manager, District Industries Centre of the Department of Industries of Government of Himachal Pradesh where the Industrial unit is registered or in other cases by the director of Industries, Himachal Pradesh or other competent authority, as the case may be. ”.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary (E&T).

बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग**अधिसूचना**

शिमला, 3 अक्टूबर, 2012

संख्या विद्युत-छ: (5)-36/2012.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल फायल, तहसील शिमला (ग्रामीण), जिला शिमला, हि0प्र0 में 132 के0वी0 कुनिहार शिमला लाईन सर्किट—।। का जुब्बड़हट्टी से मलयाणा लिलो लाईन के टावरों के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित हैं। अतएवं एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता की दृष्टि में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (4) के अधीन यह निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा-5ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	मुहाल	खसरा नम्बर	कबा (हैक्टेयर में)
शिमला	शिमला (ग्रा0)	फायल	354	00-03-36
			352	00-05-37
			कुल कित्ता- 2	कुल रकबा- 00-08-73

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव (विद्युत)।

बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग**अधिसूचना**

शिमला, 3 अक्टूबर, 2012

संख्या विद्युत-छ: (5)-39/2012.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला

अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल मैहली, तहसील शिमला (ग्रामीण), जिला शिमला, हि0प्र0 में 132 के0वी0 कुनिहार शिमला लाईन सर्किट-1। का जुब्बड़हट्टी से मलयाणा लिलो लाईन के टावरों के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित हैं। अतएवं एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता की दृष्टि में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (4) के अधीन यह निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा-5ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	मुहाल	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)
शिमला	शिमला	(ग्रा0) मैहली	686	00-04-16
			कुल कित्ता- 1	कुल रकबा- 00-04-16

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव (विद्युत)।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 5 अक्टूबर, 2012

संख्या पी.बी.डब्ल्यू(बी)एफ(5)24/2011.—यतः हिमाचल प्रदेश, के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव डी0पी0एफ0 ट्रैच्छ/49, उप-तहसील निहरी, जिला मण्डी में पण्डार-ततापानी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग मध्य क्षेत्र, मण्डी के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	उप-तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (बीघा-विस्वा) में
मण्डी	निहरी	डी0पी0एफ0 ट्रैच्छ / 49	133	0-07-19
			134	0-05-12
			135 / 1	0-01-02
			139 / 1	0-03-01
			169 / 1	0-00-18
			170 / 1	0-18-01
			171 / 1	0-00-12
			175 / 1	1-01-02
			177 / 1	1-06-19
			380 / 1	0-10-16
			382 / 1	0-02-03
			383 / 1	0-01-12
			396 / 1	0-04-17
			402 / 1	0-04-09
			403 / 1	0-03-03
			404 / 1	0-15-10
			405 / 1	0-05-14
			406 / 1	0-01-00
			407 / 1	0-01-14
			425 / 1	0-01-4
			434 / 1	0-04-16
		कुल जोड किता-21		07-02-04

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / -
सचिव(लोक निर्माण)।
